ISSN (P) : 2321-290X • (E) 2349-980X
Vol IV * Issue-II * October, 2016
RNI No. : UPBIL/2013/55327

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

Indexed with Google scholar

Impact Factor
SJIF =4.473
GIF = 0.543

The Research Series

द्विभाषीय - मासिक

Shrinkhala
शृंखला

A Multi-Disciplinary International Journal

P: ISSN NO.: 2321-290X
E: ISSN NO.: 2349-980X
RNI : UPBIL/2013/55327
VOL-IV* ISSUE-II*October-2016
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

Contents

S. No.		Page No.
1.	**Measuring Geographic Diversification: Inferences for Major Sugar Producing Nations** Sheetal & Rajiv Kumar,Hisar	01-04
2.	**On the Structure Equation** $F^4 + F^3 + F^2 + F = 0$ Lakhan Singh, Baghpat	05-06
3.	**Stock Splits and the Efficiency of the Indian Stock Market** Madhuchhanda Lahiri, West Bengal	07-17
4.	**Garlic Bulb as an Effective Eco-Friendly Strategy to Manage the Blast Disease of Paddy** Rohini Maheshwari, Rajasthan	18-20
5.	**India-Bangladesh Disputes Point** Ashish Srivastava, Allahabad & Surendra Kumar, Aurraiya	21-23
6.	**Capacity of Technological Change in Mughal India** Aruna Gogania , Dausa, Rajasthan	24-26
7.	**Women Empowerment Through Self Help Group : A Sociological Percpective** Anant Singh Jeliyang Allahabad	27-29
8.	**Prospect of Religious Harmony in 21st Century : A Study from the Perspective of Swami Vivekananda** Debarati Nandy, West Bengal	30-34
9.	**Impact of Modern Agriculture Practices on Soil Quality and Edaphic Ecosystem** Om Prakash Ambah, M.P. & Shiv Raj Singh Tomar Morena, M.P.	35-39
10.	**Major Determinants of Bangladesh Foreign Policy** Kirti Singh Chauhan, Jagatpura, Jaipur	40-45
11.	**Affecting Factor TQM in Higher Educational** Ashutosh Singh Jeliyang Allahabad, U.P.	46-49
12.	**Human Relationship in the Novels of Kamala Markandaya** Niraj Kumar Sonkar, Varanasi	50-51
13.	**Comparative Overview of the Treatment of Marginalization and Cultural Identity in the Works of Munshi Premchand and Mulk Raj Anand** Ajay Singh, Naugaon, Kasganj	52-54
14.	भारतीय जीवन बीमा व्यवसाय की तेजी में यूलिप्स एवं जीवन बीमा कम्पनियों की भूमिका पी0 के झा एवं देवेन्द्र कुमार ओझा, झारखण्ड	55-58
15.	उत्तर प्रदेश में संविद सरकारों की भूमिका (बहुजन समाज पार्टी के विशेष सन्दर्भ में) राजवीर, शाहजहाँपुर, उ.प्र.	59-62
16.	भारत पाक सम्बन्धों का संक्षिप्त इतिहास (1947 ई0–1960 ई0 के विशेष सन्दर्भ में) असमां खातून ,शाहजहाँपुर	63-65
17.	नारी के विरुद्ध अपराध : वैश्विक परिदृश्य अमरनाथ, डुमरियागंज,सिद्धार्थ नगर	66-68
18.	राजनीति का अपराधीकरण एवं पुलिस सुधार निखिल कुमार श्रीवास्तव, बछरावाँ,रायबरेली	69-73
19.	अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की भूमिका (बिलासपुर जिले के विकास खण्ड कोटा के विशेष संदर्भ में) रूकमणी गेंदले एवं प्रतिमा बैस बिलासपुर,छ.ग.	74-76
20.	स्नातक स्तर के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के विद्यार्थियों में अहिंसात्मकता का समीक्षात्मक अध्ययन आनन्द यादव हण्डिया, इलाहाबाद	77-81
21.	धर्मशास्त्र, शिक्षा और साहित्य के सन्दर्भ में महर्षि वात्स्यायन द्वारा लिखित 'काम सूत्र'का स्वरुप तथा महत्व अनिल कुमार, फरीदपुर, अलीगढ़	82-84
22.	"माउण्ट आबू पर्वतीय पर्यटन का विकास" एक विशेष अध्ययन दिनेश मीना, राजस्थान	85-87

P: ISSN NO.: 2321-290X
E: ISSN NO.: 2349-980X
RNI : UPBIL/2013/55327
VOL-IV* ISSUE-II* October-2016
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

स्थानीय शासन में महिला सहभागिता : म.प्र. का अध्ययन

सारांश

पं. जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में, "You can tell the condition of nation by looking at the status of its women."

भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि शासन में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो किन्तु देश की लगभग आधी जनसंख्या जो महिलाएँ हैं, उनकी शासन में सहभागिता आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रश्न यह है कि क्या आज जब राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नारीवादी आन्दोलन अपने अनेक सोपानों में विकसित हो रहे हैं। उस दौर में इस आधी जनसंख्या की अनदेखी कर सतत् सामाजिक – आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। लोकतंत्र के सशक्तीकरण के लिए लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे 73वें संविधान संशोधन ने सफल बनाया है। इसे 73वें संविधान संशोधन से मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति और उनकी राजनीति में सहभागिता का अध्ययन करना ही इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है।

नेहा निरंजन
वरिष्ठ प्राध्यापक,
राजनीति एवं लोक प्रशासन विभाग,
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर, मध्य प्रदेश

मुख्य शब्द : स्थानीय स्वशासन, महिला सहभागिता, 73वां संविधान संशोधन 1993, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिन्दु कोड बिल, "महिला सशक्तिकरण।

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है कि शासन में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो, देश के सत्त सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक भी है किंतु विश्व की लगभग 50% जनसंख्या जो कि महिलाएँ है, की सहभागिता आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले कुछ दशकों से महिलाओं की स्थिति और उसकी सहभागिता पर गहन चिंतन और आंदोलन हो रहे हैं राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नारीवादी आंदोलन अपने अनेक सोपानों में विकसित हो रहा है जिससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय समाज में अपितु राष्ट्रीय समाज में भी महिलाओं की जागरूकता में वृद्धि हुई है लेकिन यह विकास हर एक स्तर पर समान नहीं है चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र महिलाओं की सहभागिता अभी भी निम्न है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 145 देशों की सूची में भारत 108 वे नंबर पर है यानि दुनिया में 107 देश ऐसे है जहाँ महिलाओं की स्थिति हमारे देश से बेहतर है। यद्यपि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में लंबे समय तक हमारी राष्ट्र, प्रमुख महिला रही है और वर्तमान केन्द्र सरकार में 6 मंत्री महिलाएँ है लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के संदर्भ में देश की छवि अच्छी नहीं दिखती। चिकित्सीय सुविधाओं में विकसित देशों की तुलना में भारत अब भी काफी पीछे है। आज भी सभी गर्भवती महिलाओं के लिए समय पर प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते, भारत में प्रति एक लाख महिलाओं में से करीब 450 महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। यद्यपि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 67 फीसदी तक पहुँच चुकी है लेकिन उच्च शिक्षा के मामले में महिलाएँ अभी भी पीछे है जहाँ अमेरिका में उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत 100 है वही भारत में मात्र 24% महिलाएँ महिलाएँ उच्चशिक्षा में आ पाती है। रिसर्च के क्षेत्र में भी मात्र 14% महिलाएँ शामिल होती है जबकि भारत से ज्यादा रिसर्च में रूच्रि पाकिस्तानी महिलाओं की है आय के क्षेत्र में भी पुरूषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। संपत्ति में अधिकार के मामले में भारत की छवि खराब है यहाँ बेटियों को संपत्ति में अधिकार का कानून बनने के बावजूद संपत्ति में अधिकारी नहीं दिया जाता। 71% महिलाओं के पास इंटरनेट सुविधा नहीं है। यू.के. और जर्मनी (क्रमशः 89%, 87%) की अपेक्षा भारत में इंटरनेट महिला यूजर्स मात्र 29% ही है। कार्पोरेट जगत में महज 10.7% फर्म्स ही महिलाओं के स्वामित्व वाली है जबकि चीन (64%) इसमें कहीं आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु देश के अंदर ही राज्य स्तर पर भी काफी